January to 20th December, 1964. (These figures exclude the cases tried by Courts Martial).

P.M.'s Letters to Chief Ministers

1742. **Shri R. G. Dubey:**
Shri Yashpal Singh:
Shri Visram Prasad:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Hindi Salahkar Samiti has made recommendation that the Prime Minister should address his fortnightly letters to the Chief Ministers from the 26th January, 1965 onwards both in English and Hindi;

(b) whether they have also suggested that the letters should be only in Hindi to Chief Ministers of the Hindi-speaking States; and

(c) the other recommendations made by the Samiti?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affaire (Shri L. N. Misra): (a) The Hindi Salahkar Samiti recommended that on 26th January, 1965 or the following day, the Prime Minister may send his fortnightly letter to the Chief Ministers of all States in Hindi also.

(b) No.

(c) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3717[64].

Refixation of Seniority of Assistants

1743. **Shri R. G. Dubey:**
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Central Secretariat Assistants' Association has demanded for the refixation of their seniority according to the length of their service; and

(b) the Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Misra): (a) Yes, Sir.

(b) After full consideration, it has been decided not to revise the seniority rules.

दिल्ली में खाली प्लाटों पर अधिग्रहण नोटिस

1744. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जिन प्लाटों को अधिग्रहण करने के नोटिस दिये गये हैं उन पर इमारतें बनाने के लिये सीमेंट आदि सामान उपलब्ध करने में बड़ी कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ऐसे लोगों को और समय देने का विचार कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना समय और दिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) दल्ली को दी जाने वाली सीमेंट का अनुपात और जगहों से अधिक है । जिन व्यक्तियों की इमारतों के नक्शे सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा मंजूर हो जाते हैं । उन्हें उनकी स्वीकृत जरूरत के अनुसार किश्तों में सीमेंट दी जाती है । अन्य इमारती सामान उपलब्ध होने में कठिनाई नहीं है ।

(ख) और (ग) : भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन अधिसूचना, जिसमें सरकार का यह आशय बताया गया कि वह विकसित बस्तियों में खाली बिना बने प्लाटों को अधिग्रहीत कर लेगी, दिल्ली प्रशासन ने जारी की थी, न कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने । इसलिए